(c) how many watch service centres are expected to be set up in each State during the Seventh Plan period?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) There are 30 service centres of HMT functioning in different States as per details given in the enclosed statement laid on the Table of the House. (See below)

(b) Out of the total number of watches marketed by the Company, less than 1 per cent are received with complaints for repairs during the guarantee period. It is not in the commercial interests of HMT to disclose details regarding the number of watches repaired.

(c) The Company does not have any plans at present to open new service centres of their own. To meet the needs of the market, the company has plans to increase the number of authorised service centres.

Statement

		HMT's own service centres (Existing)
1.	Andhra Pradesh	2
2.	Assam	1
3.	Bihar	1
4.	Gujarat	1
5.	Kerala	1
6.	Madhya Pradesh	3
7.	Tamil Nadu	2
8.	Maharashtra	5
9.	Karnataka	3
10.	Orissa	1
11.	Rajasthan	1
12.	Uttar Pradesh	2
13.	West Bengal	2
14.	Jammu & Kashmir	1
15.	Haryana	1
16.	Delhi	2
17.	Chandigarh	1
		30

कोयले की मांग और पूर्ति

*176. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोयले की राज्यवार मांग कितनी है और पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष में आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य की मांग की तुलना में उसे कितना कोयला सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) मांग को सन्तोषजनक ढंग से पूरा न करने के क्या कारण हैं तथा कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है ;

(ग) राज्यों को कोयले की वर्तमान मांग को कब तक पूरा कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रेल के डिब्बों की कमी के कारण कोयले को समय पर नहीं उठाया जा सका; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) देश में कोयले की कुल मांग का तथा बिजलीघरों, रेलवे, इस्पात कारखानों, सीमेंट कारखानों और उर्वरक कारखानों जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों की मांग का निर्धारण योजना आयोग करता है । अन्य विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग का निर्धारण संबंधित प्रायोजन प्राधिकारी करते हैं । प्रायोजन प्राधिकारी राज्यवार नहीं बल्कि उद्योग-वार हैं जैसे तकनीकी विकास महानिदेशालय, इंडियन शुगर मिल्स ऐसोसिएशन, इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन फार टैक्सटाइल मिल्स, आदि । इसलिए मांग का केवल क्षेत्र-वार निर्धारण किया जाता है और उसी के अनुसार प्रायोजन किया जाता है । कोयला कंपनियां

प्रायोजित मात्रा उपभोक्ताओं को देने का प्रस्ताव कर देती हैं और उपभोक्ता चाहें तो इसे रेल से ले जाएं, या सड़क से ले जाएं अथवा दोनों से ले जाएं। राज्य सरकारों को रेलवे वैगनों का कोटा देती हैं और राज्य सरकारें अपने राज्य में स्थित छोटे उद्योगों की जरूरतों का प्रायोजन करती हैं। परन्तु कभी-कभी रेल द्वारा उपभोक्ताओं को कोयला सप्लाई मांग की तुलना में कम हो जाती है जिसका कारण वैगनों की कम उपलब्धि अथवा रेल से कोयले के लदान में कठिनाइयां होती हैं। इसके अलावा, यह बात भी है कि रेलवे की वरीयता यातायात अनुसूची में रेल संचालन के लिए दी गई प्राथमिकता के अनुसार कोयला, इस्पात कारखानों, बिजलीघरों, सीमेंट कारखानों आदि को अधिक उच्चतर वरीयता के आधार पर दिया जाता है इसलिए रेल द्वारा कोयले के सँचालन में जिन अन्य उपभोक्ताओं को निचली प्राथमिकता प्राप्त होता है उन्हें उसी अनुपात में रेल से कम कोयला मिलता है। फिर भी रेल से संचालन में जो कमी रह जाती है उसे सड़क द्वारा ले जाने के लिए कोयला देकर पूरा कर दिया जाता है।

चूंकि विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों के प्रायोजन प्राधिकारी अलग-अलग हैं, इसलिए राज्यों में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं की मांग के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। फिर भी वर्ष 1985-86 और 1986 87 में कोयले की मांग की तुलना में क्षेत्र-वार प्रेषण का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकड़े मिलियन टनों में)

क्र० सं०	क्षेत्र	निर्धारित मांग (वार्षिक योजना लक्ष्य) 1985-86	निर्धारित मांग (वार्षिक योजना लक्ष्य) 1986-87	वास्तविक उठान 1985-86	वास्तविक उठान 86-87 (अन्तिम)
1.	इस्पात और कोक भट्ठियां	30.40	30.35	24.52	23.46
2.	बिजली :				
	(1) कच्चा कोयला	72.35	83.41	75.11	81.53
	(2) मिड्लिंग्स	(3.64)	(4.17)	(2.22)	(2.03)
3.	रेल	9.60	8.70	9.10	7.80
4.	सीमेंट	8.75	9.33	7.90	8.47
5.	उर्वरक	5.00	5.20	3.98	4.45
6.	साफ्ट कोक निर्माण	3.50	4.00	2.29	2.05
7.	निर्यात	0.20	0.20	0.22	0.21
8.	ईंट भट्ठा/अन्य	24.20+	26.91+	27.01+	30.44
	ग्रहीत बिजलीघर	5.80	4.50 (1.54)	(0.89)	
9.	कोलियरी उपभोग	4.00	4.00	4.11	3.99
	जोड़	163.80 (3.64)	176.60 (5.71)	154.24 (3.11)	162.40 (2.03)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वाशरी मिडलिंग के हैं।)

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न क्षेत्रों की मांग ज्यादातर पूरी ही की जा रही है। फिर भी विभिन्न कारणों से कुछ क्षेत्रों में सप्लाई में कमी हुई है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए समय-समय पर सुधार की कार्रवाई की गई है।

Cement Industry

*177. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the cement industry is facing problem of power supply in some of the major cement producing states and the coal used by the plants has been found to be of inferior quality;

(b) if so, what steps Government have taken to boost the cement production;

(c) what was the total production of cement during the years 1985-86 and 1986-87;

(d) what would be the production target for 1987-88;

(e) whether Government have any proposals to open new cement factories in the country; and

(f) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Cement plants located in certain major cement producing States and particularly in the States of Karnataka, Tamil Nadu and Rajasthan and recentlly Andhra Pradesh have been facing problem of power cuts/short supply of power. In regard to the quality of coal, there have been some complaints about the size of coal, low calorific value and presence of extraneous material in the coal supplied.

(b) In order to overcome power shortage cement industry has been advised to instal captive power plants to meet about 40 per cent of their power requirement. Almost all the cement units in power deficit States have installed captive power plants. The concerned State Governments have also been requested to minimise power-cuts on cement factories. With a view to ensure proper sizing and removal of extraneous materials, coal handling plants are being constructed at the collieries. Independent quality control organisations have also been set up in each coal company to monitor the quality of coal supplied. With a view to overcome the infrastructural constraints, the Department of Industrial Development as well as the Development Commissioner for Cement Industry have been constantly in touch with the concerned agencies to ensure that the constraints are removed/minimised expeditiously. As a result of these efforts, the production of cement has been steadily going up. As against production of 18.56 million tonnes in 1980-81, the production during the year 1986-87 was 36.50 million tonnes.

(c) The production during 1985-86 and 1986-87 was 33.10 million and 36.50 million tonnes respectively.

(d) A production target of 42.50 million tonnes have been fixed for 1987-88.

(e) and (f) The following large cement plants are expected to be commissioned during 1987-88:—

Statement

Name of the Company	Location	Capacity (Lakh tonnes)
Cement Corporation of India Ltd.	Tandur, A.P.	10.00
Shriram Fertilizers & Chemicals	Kota, Rajasthan	2.00
Cement Corporation of Gujarat	Junagadh, Gujarat	10.00
Raymond Wollen Mills Ltd.	Bilaspur, M.P.	3.00*
J.K. Synthetics Ltd.	Chittorgarh Rajasthan	4.00*
Orissa Cements	Rajgangpur Orissa	1.24*
Mysore Cements Ltd.	Damoh, M.P.	4.75*
	TOTAL	34.99

*Substantial Expansion